MR. CHAIRMAN: Q. No. 145.

Infrastructure to Encourage Coastal Shipping

*145. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:†

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Shipping Board has been impressing upon the Government to provide necessary infrastructure to encourage Coastal Shipping;

(b) whether the National Transport Policy Committee has also strongly advocated the same and has assessed that the Coastal Shipping would be much cheaper than the rail and the road transport; and

(c) if so, what action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The National Transport Policy Committee had envisaged a role for Coastal Shipping mainly in catering to project oriented traffic. They had also expressed the view that Coastal Shipping had lost its competitiveness to rail and road transport.

(c) The main steps taken so far to encourage Coastal Shipping are simplification of custom procedure in respect of coastal vessels, delegation of powers to fix/revise coastal tariff, permission to acquire fresh tonnage for coastal shipping with reference to the age and fuel efficiency of the vessels and concessional rates for coastal vessels in respect of port dues and port charges. For Thermal Power Stations located in the eastern and western coasts of South India, coastal movement of coal from Haldia, Paradip and Vizag is actively encouraged as a matter of conscious Government policy.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Chaturanan Mishra.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने "बी" भाग में जवाब दिया है कि

They had also expressed the view that Coastal Shipping had lost its competitiveness to rail and road transport.

इसलिए क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह कैसे कम्पिटिटिव लौस कर गया और किन फैक्टर्स के चलते यह हुआ ? कैसे रेल का भाडा शिपिंग के भाड़े से ज्यादा है या कम है, इसके बारे में क्या आंकड़े हैं ? सरकार उनको उपलब्ध कराएगी ?

SHRI MANUBHAI KOTADIA: Generally, the comparison between road transport cost, the rail transport cost and the shipping cost is made by some experts. The experts have come to the conclusion that cases where the distance is the same, road or rail transport is cheaper than costal transport.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय मैंने क्या पूछा था और क्या जवाब आया है हमने फैक्टर्स और फीगर्स पूछे थे। अगर मंत्री महोदय के पास नहीं हैं ...(व्यवधान)

SHRI S. JAIPAL REDDY: The Minister was absent-minded... (*Interruptions*) ....

MR. CHAIRMAN: He is not absent-minded. He could not follow the Bihari Hindi and so it become difficult for him to understand... (*Interruptions*)...

श्री चतुरानन मिश्र : एक तो खतरा है कि लेटर आन आप रहे या नहीं रहें ...(व्यवधान)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, I think a training course for the Minister ...(*Interruptions*)... should be there....(*Interruptions*)...

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि बाद में भेज देंगे। मैं चाहता हूं कि बाद में आप रहें। कहीं आपको बाहर भेज दे तो क्या होगा। मैं तो चाहता हूं कि बाद में भी आप रहें। **(व्यवधान)**

श्री सभापति : अब तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है।

श्री चतुरानन मिश्र : दूसरी बात...

श्री सभापति : अब आप मत बोलिए। ब्रहमा जी का आशीर्वाद हो गया।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, अब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि...

श्री सभापति : पहले आप चाहते हैं कि ये रहें फिर उसके बाद और क्या चाहते हैं आप ?

श्री चतुरानन मिश्र : रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके लिए तो उनके ब्रहमा दूसरे हैं। राजीव जी के चरणोंगत रहें तभी रह सकते हैं।

श्री सभापति : ब्रहमा का आशीर्वाद हो गया ...**(व्यवधान)**... चतुरानन ब्रहमा का नाम है ...**(व्यवधान)**...

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, इस सवाल का दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि रेल, रोड, कोस्टल शिपिंग और हमारे लिए यह फायदेमंद होगा अगर कोस्टल शिपिंग लाइन ट्रैफिक हम चलायें। इसलिए मैं कहा रहा हूं, आप सीमेंट की प्राइसेज ले लीजिए। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की सीमेंट प्राइस में 10 से 15 रुपये का फर्क पड़ जाता है। कम से कम 10 रुपये का फर्क तो पड़ ही जाता है। अगर आप उसको शिपिंग से यहाँ पहुंचा देते तो आसानी से वह यहां पहुंच सकता था और उसकी प्राइस हम फाइट आउट कर सकते थे। दूसरी बात, जो पैसेंजर ट्रैफिक है वह हायली कंजेस्टेड है। इसलिए अगर कोस्टल शिपिंग से रोड का ट्रांसपोर्ट हम कर दें तब भी हम इसको आसान बना सकते हैं। इसलिए स्टील या दूसरे सामानों को देखते हुए सरकार को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए कि कैसे हम जो कंजेस्टेड लाइन हैं, रेल की उसको हम यील्ड कर सकें, हल्का कर सकें। ऐसा करके ही हम पूरे व्यवसाय की मदद कर सकते हैं। लेकिन इस दृष्टिकोण से आपकी ट्रांसपोर्ट कमेटी ने विचार नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री मनुभाई कोटाडिया : सभापति जी, माननीय सदस्य की चिंता सही है और मैं इसका सहभागी बनना चाहता हूं। सभापति जी, ट्रांसपोर्ट कमीशन ने जो सुझाव दिया है It was of a general nature. आज हमारे रोड पर जो बर्डन बढ़ रहा है, रेल पर जो बर्डन बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए जहां सस्ता हो वहां कोस्टल ट्रांसपोर्ट से माल और पैसेंजर की हेराफेरी की जाय ताकि रोड या रेल पर जो आज बर्डन है उसको कम कर सकें यह सही बात है और जहां एज फार पासिबल हो उधर हम कुछ सस्ता भी दे सके हैं यह भी सही बात है। इसके बारे में सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं और कदम उठाने के बाद मैं माननीय सदस्य को यह फिगर देना चाहता हूं कि 1981 में हमारा जो कोस्टल ट्रांसपोर्ट था वह करीब 4.5 मिलियन टन का था In eight years, in 1989, we have already crossed 24,000 kms .on traffic. तो चार मिलियन टन से हम 24 मिलियन टन तक पहुंच गये हैं।

श्री सभापति : 6 गुना हो गया है।

श्री मनुभाई कोटाडिया : फिर भी हम इससे संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। इसके बारे में हमें भी चिंता है और इसको करने की जरूरत है। पैसेंजर ट्रैफिक के बारे में आज जो स्थिति है आज वह वायेबल नहीं है, उसकी वायेबिलिटी नहीं है। जहां डिस्टेंस कम है, एक्जाम्पल के लिए सौराष्ट्र कोस्ट से बंबई जाने के लिए इसको चालू करना बहुत सही होगा क्योंकि the distance from Saurashtra will be about 270 kms. while by road it is more than 900 kms.

तो इसमें तो सही हो सकता है लेकिन बम्बई से गोवा और बम्बई से मंगलूर चलायेंगे तो वह सही नहीं होगा क्योंकि यहां पर कस्टम क्लेयरेंस आदि जो विधि है वह बहुत लंबी है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि कोस्टल शिपिंग को जितना ज्यादा ला सकते हैं उतना लाने की कोशिश करेंगे।

SHRI SOM PAL: I would like to know from the Government whether in order to improve the economic viability of our ports there is a proposal under consideration to permit ships with foreign clients to visit Indian ports, to avail transit facilities and for container aggregation and whether there is a proposal to suitably amend the law to facilitate that.

SHRI MANUBHAI KOTADIA: Sir, recently we had some discussion in our Port Trust Chairmen's meeting and to amend this is under active consideration of the Government.

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, the hon. Minister has stated or rather assured the hon. Member, Shri Chaturanan Mishra, that he would supply information as to the relative cost efficiency of coastal shipping transport compared to rail transport and road transport. But apart from that fact, Sir, you will appreciate, and I hope the Minister would also appreciate, that there is a recession in the shipping industry as such, and so the shipping industry also requires a sort of diversion from high sea to coastal shipping. And there are hazards of the rail bookings and road bookings. In view of these factors, the hazards the Railways and road transport are facing, they have got certain stagnancy also. The optimum they have reached. In view of the recession in the shipping industry as such, would the Government consider purposely that the coastal shipping transport is encouraged and improved so that the traders and passengers can take recourse to coastal shipping more and more.

श्री मनुभाई कोटाडिया: सभापति महोदय, मैंने मिश्रा जी के प्रश्न के जवाब में कहा है कि कोस्टल शिपिंग इंडस्ट्री को जितना बढ़ावा दिया जाना चाहिये था उतना नहीं दिया गया है। अभी उसके बारे में बहुत स्कोप है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर हम पूरी तरह से सोचेंगे।

(Q. Nos. 146 to 148 — Hon. Members absent)

*146. [*The questioner (Miss Saroj Khaparde) was absent. For answer* vide *Col.* 33—35 infra]

*147. [*The questioner (Shri Prabhakar Rai Kalvala) was absent. For answer* vide *Col.* 35 infra]

*148. [*The questioner (Shri Jagdish Jani) was absent. For answer vide cols.* 35-36 *infra*]

Privatisation of Telecommunications Sector

*149. SHRI J. P. JAVALI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the International Finance Corporation (I.F.C.) has recently suggested the privatisation of a part of the telecommunications sector in India as it is among the poorest in the world; and

(b) if so, what are the details of the proposal and the action proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. SANJAY SINGH): (a) No, Sir. No suggestions have been received from I.F.C. in this regard.

(b) Does not arise.

SHRI J. P. JAVALI: My question to the Government was whether it is a fact that the International Finance Corporation (IFC) has recently suggested the privartisation of a part of the telecommunications sector in India as it is among the poorest in the world. I would like to know from the hon. Minister whether